(c) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI S. R. BOMMAI): (a) Yes, Sir.

(b) and (c) No, Sir. The correspondence is closed to scholarly scrutiny due to a stipulation in this regard by the depositor.

दिल्ली विश्वविद्यालयों में आरक्षण नीति पर सम्मेलन

2175. **श्री सच्चिदानन्द:**

श्री जलालुदीन अंसारी:

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विश्वविद्यालयों में शिक्षण और शिक्षणोत्तर पदों के लिये अन्य पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों हेतु आरक्षण नीति के विषय पर दिसम्बर, 1996 अथवा जनवरी, 1987 में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष द्वारा भी भाग लिया गया था;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्मेलन में लिये गये निर्णयों का ब्यौरा क्या है तथा उनके कार्यान्वयन की रूपरेखा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया): (क) से (ग) हाल ही में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष ने अध्यापन और गैर अध्यापन पदों पर नियुक्ति हेतु आरक्षण नीति पर दिल्ली विश्वविद्यालय के अधिकारियों और इसके कालेजों के प्रधानाचार्यों से व्यापक स्तर पर बहुत उपयोगी बातचीत की है। आशा है कि इस संबंध में विश्वविद्यालय की विद्यमान नीति को अध्यक्ष द्वारा दी गई रूपरेखाओं और दिशा-निर्देशों पर आगे सुदृढ़ किया जाएगा।

Villages Lacking Basic Educational Facilities

2176. SHRI JAGANNATH SINGH:

SHRI SANJAY NIRUPAM:

Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether Government have identified the villages in the country which still have not been provided the basic educational facilities like primary and middle schools; and

(b) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF EDUCATION IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI MUHI RAM SAIKIA): (a) All India Educational Survey are conducted periodically by States under the aegis of the National Council of Educational Research and Training (NCERT) to assess the availability of existing schooling facilities at different stages of education.

(b) According to the fifth All-India Educational Survey, there were 1,83,208 revenue villages without a primary school.

चट्टोपाध्याय आयोग की सिफारिशें

2177. **श्री सुन्दर सिंह भंडारी: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:**

(क) क्या चट्टोपाध्याय आयोग की प्रमुख सिफारिशें क्या हैं;

(ख) उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) सरकार राष्ट्रीय शिक्षक आयोग की सिफारिशों को कब तक लागू करेगी?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया): (क) से (ग) 1985 में प्रस्तुत चट्टोपाध्याय आयोग की रिपोर्ट में 138 सिफारिशें थीं जिनमें से अनेक व्यापक टिप्पणियों के स्वरूप में थीं जिनमें एक राष्ट्रीय कोर-पाठ्यक्रम, व्यावसायीकरण, प्रारम्भिक शिक्षा को सर्वसुलभ कराना, शिक्षकों के स्तर कार्य दशाएं और कल्याण, शिक्षकों की आपूर्ति, भर्ती और प्रशिक्षण, शिक्षकों के प्रति समाज की आशाएं इत्यादि संबंधी आवश्यकता शामिल है। आयोग की सिफारिशों पर की गई कार्रवाई संबंधी रिपोर्ट पहले ही दिनांक 30.7.1991 को सभा पटल पर रख दी गई है।

इन सिफारिशों पर पहले ही सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति और कार्य योजना (1992) में यथा संशोधित बनाने और शिक्षकों के दिनांक 1-1-1986 से लागू संशोधित वेतनमान और परिलब्धियां अधिसूचित करते समय भी ध्यान में रखा गया है।